**Title:** Regarding preparation of the final list of IPS cadres for posting of police officers in the States of Madhya Pradesh and Chhatisgarh without further delay.

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) :** अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस अधिकारियों से जुड़े एक मामले को उठा रहा हूं। मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद आई.पी.एस. अधिकारियों के जो कैडर सुनिश्चित होने थे, उस प्रक्रिया को प्रारम्भ हुए अभी डेढ़ वर्ा पूरा हुआ। पहली बार जो सूची जारी हुई, उस सूची को फिर से परिवर्तित किया गया, गृह मंत्रालय के सामने सरकार ने पहुंचाया और उसका जो क्रम तय था कि कुछ आरक्षण के तहत जो अधिकारी जाने थे, उन मान्यताओं को पूरा नहीं किया, परिणाम यह हुआ कि इसको पिछले सप्ताह 40 आई.पी.एस. अधिकारियों की फिर से सूची जारी करके उनको सो कॉज नोटिस दिया गया। इस सारी परिस्थिति के खिलाफ आई.पी.एस. अधिकारी कैट के सामने पिटीशन में गये हैं। दो बातें उससे बहुत गम्भीरतम हुई हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति नक्सलवादी आन्दोलन के कारण उनका हतोत्साहित होना, उनकी अनिश्चितता खतरनाक स्थिति में है। उधर उससे दूसरी जो परिस्थिति पैदा हुई है कि कैट में जो पिटीशन आई.पी.एस. अधिकारियों ने की है, यदि कल कैट कोई निर्णय देगा तो चौथी बार फिर से इस सूची में परिवर्तन करना पड़ेगा।

मैं आपके माध्मय से गृह मंत्रालय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आई.पी.एस. अधिकारियों की ऐसी अनिश्चितता छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे प्रान्त में, जहां नक्सल वादी आन्दोलन आज मुंह बाये खड़ा है, वह सुनिश्चित होना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार ने जो नियमों का पालन न करते हुए अपनी मनमर्जी की सूची भेजी है, उसके कारण पुनः पांचवीं बार उन आई.पी.एस. अधिकारियों की सूची बदल सकती है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि उस पर तत्काल कदम उठाकर उस सूची को दुरुस्त करके तत्काल कार्रवाई करे।